INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD)
© 2026 IJNRD | Volume 11, Issue 2, February 2026 | ISSN: 2456-4184 | IJNRD.ORG

नई अर्थव्यवस्था में स्थानीय भाषाओं की व्यवसायिक भूमिका

श्री. जनार्दन नामदेव वाघ
सह. प्राध्यापक, हिंदी विभाग
जनसेवा फौन्डेशन कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, शेंडी (भंडारदरा)
तहसील–अकोले, जिला–अहिल्यानगर
भ्रमणध्वनी : 9403651565
ई-मेल : waghjanardan@gmail.com

सार

नई अर्थव्यवस्था में डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, ई-कॉमर्स, प्लेटफ़ॉर्म आधारित व्यापार, स्टार्ट-अप संस्कृति तथा वैश्वीकरण ने व्यवसाय की संरचना और कार्यप्रणाली को मूल रूप से परिवर्तित कर दिया है। इस परिवर्तन के साथ भाषा की भूमिका केवल संप्रेषण तक सीमित न रहकर व्यवसायिक रणनीति का एक केंद्रीय घटक बन गई है। यद्यपि लंबे समय तक अंग्रेज़ी को व्यापार और प्रबंधन की प्रमुख भाषा माना जाता रहा, किंतु वर्तमान परिदृश्य में स्थानीय भाषाएँ उपभोक्ता पहुँच, बाज़ार विस्तार, ब्रांड विश्वास और आर्थिक समावेशन का प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से यह अध्ययन करता है कि नई अर्थव्यवस्था में स्थानीय भाषाएँ किस प्रकार व्यवसायिक सफलता और समावेशी विकास को सुनिश्चित कर रही हैं।

कुंजी शब्द: नई अर्थव्यवस्था, स्थानीय भाषाएँ, डिजिटल व्यापार, आर्थिक समावेशन

भूमिका

इक्कीसवीं सदी की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को 'नई अर्थव्यवस्था' के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, ज्ञान-आधारित उद्योगों और वैश्वीकरण की निर्णायक भूमिका है। थॉमस एल. फ्रीडमैन ने यह स्पष्ट किया है कि आधुनिक विश्व में स्थानीय और वैश्विक बाज़ार परस्पर गहराई से जुड़े हुए हैं। [1]

इस संदर्भ में संचार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है और भाषा व्यवसाय की सफलता का प्रमुख आधार बनती है। भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकांश जनसंख्या अंग्रेज़ी में दक्ष नहीं है, केवल अंग्रेज़ी-आधारित व्यापार मॉडल समावेशी विकास में बाधक सिद्ध होता है। इसलिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग नई अर्थव्यवस्था को व्यापक और लोकतांत्रिक बनाता है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध-पत्र गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है। इस अध्ययन का उद्देश्य नई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय भाषाओं की व्यवसायिक भूमिका का सैद्धांतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विश्लेषण करना है। शोध में प्राथमिक आँकड़ों के स्थान पर द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, क्योंकि विषय का स्वरूप वैचारिक और प्रवृत्तिगत है।

अनुसंधान सामग्री पुस्तकों, शोध-पत्रिकाओं, सरकारी एवं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों से संकलित की गई है। थॉमस एल. फ्रीडमैन, मैनुएल कास्टेल्स, डेविड क्रिस्टल और अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों के विचारों को सैद्धांतिक आधार के रूप में ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त NASSCOM, विश्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, यूनेस्को तथा भारत सरकार की रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन में व्याख्यात्मक एवं तुलनात्मक पद्धति अपनाते हुए विषयवस्तु-आधारित विश्लेषण किया गया है।

नई अर्थव्यवस्था की अवधारणा

नई अर्थव्यवस्था उस आर्थिक ढाँचे को संदर्भित करती है जिसमें सूचना, ज्ञान और नेटवर्क आधारित संरचनाएँ केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। मैनुएल कास्टेल्स के अनुसार आधुनिक समाज 'नेटवर्क सोसाइटी' में परिवर्तित हो चुका है, जहाँ सूचना का प्रवाह ही आर्थिक शक्ति का प्रमुख स्रोत है।[2]

इस व्यवस्था में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, ई-कॉमर्स और सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उपभोक्ता-केंद्रित दृष्टिकोण इसकी प्रमुख विशेषता है।

स्थानीय भाषाओं का अर्थ और महत्व

स्थानीय भाषाएँ वे भाषाएँ हैं जिनका प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष के लोग दैनिक जीवन में करते हैं। भारत में हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएँ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। डेविड क्रिस्टल ने यह स्पष्ट किया है कि इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों ने स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को नई गति प्रदान की है।[3]

अमर्त्य सेन के अनुसार विकास तभी सार्थक होता है जब वह व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करे।[4] स्थानीय भाषाएँ इस सहभागिता को संभव बनाती हैं।

नई अर्थव्यवस्था में स्थानीय भाषाओं की व्यवसायिक भूमिका

(क) उपभोक्ता पहुँच और बाज़ार विस्तार

फ़्रीडमैन के अनुसार वैश्वीकरण ने स्थानीय बाज़ारों को वैश्विक मंच प्रदान किया है।[5] उपभोक्ता जब अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त करता है, तो उसका विश्वास बढ़ता है।

(ख) ई-कॉमर्स और स्थानीय भाषाएँ

NASSCOM की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय भाषाओं में उपलब्ध डिजिटल सेवाओं से ई-कॉमर्स कंपनियों का उपभोक्ता आधार उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।[6]

(ग) स्टार्ट-अप्स और नवाचार

स्थानीय भाषा आधारित स्टार्ट-अप्स डिजिटल शिक्षा, हेल्थ-टेक और कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से व्यापक जनसमूह तक पहुँच बना रहे हैं। क्रिस्टल ने इंटरनेट पर भाषाओं की बदलती भूमिका का विश्लेषण किया है।[7]

(घ) डिजिटल विज्ञापन और ब्रांडिंग

स्थानीय भाषाओं में किए गए डिजिटल विज्ञापन उपभोक्ता के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करते हैं और ब्रांड विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं।

6. आर्थिक समावेशन में स्थानीय भाषाओं की भूमिका

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल तकनीक आर्थिक अवसरों को व्यापक बनाने में सहायक होती है।[8] भारत में बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं की जानकारी स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने से वंचित वर्ग भी औपचारिक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ सके हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी स्थानीय भाषाओं में वित्तीय सेवाओं के महत्व को स्वीकार किया है।[9]

7. चुनौतियाँ और सीमाएँ

स्थानीय भाषाओं के व्यवसायिक उपयोग में तकनीकी शब्दावली की कमी, गुणवत्तापूर्ण अनुवाद का अभाव तथा बहुभाषी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की लागत जैसी समस्याएँ हैं। यूनेस्को ने बहुभाषी शिक्षा और डिजिटल सामग्री के विकास पर बल दिया है।[10]

8. भविष्य की संभावनाएँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया गया है।[11] कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन अनुवाद तकनीकें भविष्य में स्थानीय भाषाओं की व्यवसायिक भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएँगी।

9. निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि नई अर्थव्यवस्था में स्थानीय भाषाएँ केवल सहायक माध्यम नहीं, बल्कि व्यवसायिक सफलता का आधार बन चुकी हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए स्थानीय भाषाओं को व्यवसाय और नीति-निर्माण के केंद्र में रखना अनिवार्य है।

संदर्भ सूची :

1. Friedman, T. L. (2005). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. Farrar, Straus and Giroux.
2. Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.
3. Crystal, D. (2010). Language and the Internet. Cambridge University Press.
4. Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
5. Friedman, T. L. (2005). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century. Farrar, Straus and Giroux.
6. NASSCOM. (2019). Indian Tech Start-up Ecosystem Report. New Delhi: NASSCOM.
7. Crystal, D. (2010). Language and the Internet. Cambridge University Press.
8. World Bank. (2016). World Development Report: Digital Dividends. Washington, DC: World Bank.
9. Reserve Bank of India. (2021). Financial Inclusion and Digital Payments in India. RBI Publications.
10. UNESCO. (2003). Education in a Multilingual World. Paris: UNESCO.
11. Government of India. (2020). National Education Policy 2020. Ministry of Education.

• **Copyright & License:**
© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.